

संपादकीय

कानून और व्यवस्था के लिए समर्पया

मानव स्वास्थ्य और भलाई के लिए प्रमुख खतरों में, हिंसा या शायद ही कभी सूचीबद्ध किया जाता है। इसे ज्यादातर कानून अनुसार समझा जाता है कि यह व्यवस्था की समस्या के रूप में देखा जाता है जब यह किसी देश या भीतर होती है या युद्ध के रूप में जब यह देशों के बीच संघर्ष होता है। आतंकवाद, जिसकी उत्पत्ति घरेलू या विदेशी हो सकती है, हिंसा का भी परिणाम होता है, जो पुलिस या सैन्य प्रतिक्रिया को आमतिरिक्त करता है। जबकि डॉक्टरों और नर्सों को हिंसा के पीड़ितों का इलाज करने के लिए बुलाया जाता है, चिकित्सा पेशे को शायद ही कभी किया जाता है। समुदाय में होने वाली हिंसा के परिमाण और प्रमुख कारणों की पहचान करने में लगाया जाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी समय—सम्बन्धित पर दुनिया भर में विभिन्न स्वास्थ्य विकारों के कारण होने वाली मौतों और विकलांगता के विभिन्न कारणों का अनुमान लगाती है। यह रिपोर्ट करती है कि चोटों (समय से पहले मृत्यु या लंबे समय तक विकलांगता के कारण कुल बीमारी का बोझ पिछले तीन दशकों में दुनिया भर में बढ़ गया है और 2020 में 247.7 मिलियन विकलांगता—समायोजित जीवन वर्षों का नुकसान हुआ है। तब से घरेलू और क्षेत्रीय संघर्षों द्वारा स्तरों के साथ, चोटों के कारण बीमारी का बोझ 2023 में और अधिक होने की संभावना है (अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है)। हालांकि, ये अनुमान वास्तविकता से कम होने की संभावना है, क्योंकि हिंसा के कई मामले पुलिस को रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, जो ऐसे डेटा को बनाए रखते हैं और रिपोर्ट करते हैं। घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएँ और स्कूल में बदमाशी से होने वाली चोटें चोट के उन कारणों में से हैं जो पुलिस के ध्यान में नहीं आ सकते हैं। एसिड अटैक, या अपराध और आपराधिक जबरन वसूली के पीड़ित भी अक्सर पुलिस को रिपोर्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संपर्क न करने की धमकी दी जाती है। किसी भी कारण से होने वाली हिंसा के केवल व्यक्तिगत चिंता का विषय नहीं है। न ही यह केवल पुलिस द्वारा संभाली जाने वाली समस्या है जो अपराधियों को पकड़ने और उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने का प्रयास करती है। पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए समुदाय में हिंसा कारणों की पहचान की जानी चाहिए। यह सच है कि कारण घरेलू या सांप्रदायिक, राजनीतिक या संपत्ति से संबंधित हैं। हिंसक कृतियों को रोकने और कमज़ोर पीड़ितों की रक्षा करने के लिए हिंसा के स्तर पीड़ितों के प्रकार और साथ ही मुख्य कारणों की पहचान की जानी चाहिए। हालांकि, इस प्रयास के लिए हिंसा से संबंधित डेटा जितना संभव हो उतना पूर्ण और स्थान—विशिष्ट होना चाहिए। यदि चोटें गंभीर हैं, तो पीड़ित के चिकित्सा सहायता लेने की संभावना है, जबकि पुलिस को घटना के बारे में पता भी नहीं हो सकता है। यह देखना चाहिए कि अस्पताल के आपातकालीन विभाग में रिपोर्ट की गई घटनाएँ में से केवल 23 प्रतिशत ही उसी अवधि में एवन और समरसेट के क्षेत्र में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं। इस बात से चिंतित कि डेटा विसंगति का इतना उच्च स्तर समस्या की भयावहता को कम आंकने और डेटा ब्लाइंड स्पॉट की ओर ले जा सकता है जो रोकथाम के उपायों को संबंधित कर सकता है, कार्डिफ, यूके में एक नई पहल शुरू की गयी है। यह हिंसा से संबंधित चोटों के पुलिस रिकॉर्ड को अस्पतालों में दर्ज किए गए रिकॉर्ड के साथ मिलाता है और हिंसा से संबंधित चोटों का सामना करने वाले लोगों की संख्या का अधिक पूर्ण अनुमान प्राप्त करने और मुख्य कारणों की यथासंभव सटीक सूची बनाने के लिए संयोजित करता है। यह पहल कोयला खनिकों की हड्डतानाओं और फुटबॉल मैचों के आसपास झड़पों से संबंधित हिंसा को घटनाओं से भी प्रेरित थी। घायल लोगों और अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों के पुलिस रिकॉर्ड के बीच विसंगतियों के कारण 1980 के दशक की शुरुआत में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में प्रशिक्षित डॉ. जोनाथन शेपर्ड ने एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसे 1997 कार्डिफ मॉडल फॉर वायलेंस प्रिवेंशन के नाम से जाना जाता है। कार्डिफ मॉडल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, पुलिस और स्थानीय समुदाय को एक साथ लाता है। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेटिंग्स (जैसे अस्पताल) में, हिंसा से संबंधित चोट के डेटा एकत्र किए जाते हैं, इनमें आपातकालीन कक्ष के कर्मचारियों द्वारा एकत्र की गई चोटों का स्थान, समय, तिथि और तत्र (हमले का प्रकार और हथियार का शामिल हैं)। गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसा के पीड़ितों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए, अन्य व्यक्तिगत पहचानकर्ता (नाम, जन्म तिथि, सामाजिक सुरक्षा संख्या) डेटाबेस से हटा दिए जाते हैं, जिन्हें पुलिस डेटाबेस के साथ मिलान अविलिय किया जाएगा। संयुक्त डेटाबेस का विश्लेषण हिंसक घटनाओं की भयावहता और पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप चोट लगती है। विश्लेषण किए गए डेटा द्वारा स्थानीय समुदाय के साथ साझा किया जाता है, जिसमें पुलिस अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दोनों सामुदायिक बोर्डों के साथ बातचीत करते हैं। भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की रणनीति द्विग्रस्त, पैटर्न और स्थानीय हॉटस्पॉट को पहचान कर एक साथ विकसित की जाती है। मॉडल का मूल्यांकन किया गया है अंत में शहरी हिंसा और परिणामी चोटों को कम करने में प्रभावशाली साबित हुआ है। कार्डिफ में, संयुक्त डेटा द्वारा पहचाने गए हॉटस्पॉट को शामिल करने के लिए साप्ताहिक आधार पर पुलिस गश्ती में जिसके समायोजित किया गया था।

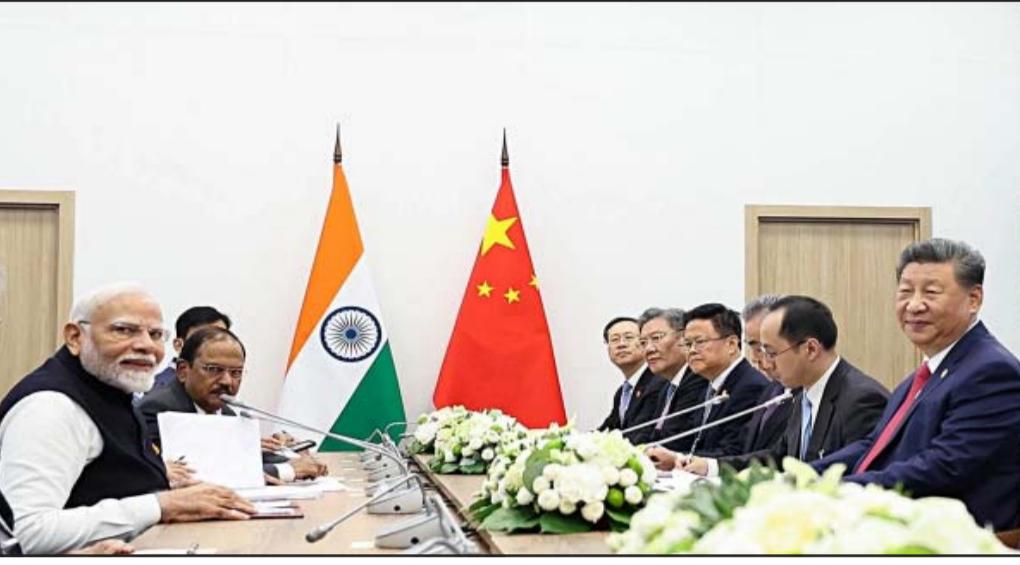
उमेश

लद्धाख सामा पर गश्ता का लकड़ा
भारत और चीन के बीच सहमति
बन तो गई है, लेकिन उस पर
अंख मूंदकर भरोसा करना जल्दबाजी
और नासमझी होगी। अतीत में चीन
के रवैये को देखते हुए भारतीय
सेनाध्यक्ष जनरल उपर्युक्त द्विवेदी का
यह कहना समीचीन ही है कि भरोसा
बहाली में समय लगेगा। रुस-यूक्रेन
और इजराइल -हिजबुल्ला संघर्ष
के संदर्भ में भारत और चीन के बीच
हुए इस समझौते को बेहतर परिणति
ही माना जाना चाहिए। 15 और 16
जून 2020 की रात को बिना हथियारों
के भारतीय सैनिकों ने लाल सेना के
भले ही दांत खट्टे कर दिए, लेकिन
भारतीय विपक्षी दलों ने उस मौके
को उत्तेजना की राजनीति के लिए
बेहतर मौके के रूप में लिया था।
महज एक साल पहले ही तमिलनाडु
में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग
के साथ प्रधानमंत्री मोदी की चर्चित
मुलाकात का हवाला देते हुए विपक्षी
दलों ने मोदी सरकार पर दबाव
बढ़ाने की कोशिश की थी। उनकी
मंशा चीन के साथ सीधी युद्ध करने
के लिए सरकार को उकसाना रहा।
बेशक 1962 जैसी स्थिति नहीं रही
तब से लेकर भारत ने सैनिक और
आर्थिक मोर्चे पर लबा सफर तय
कर लिया है। वहीं चीन इस अवधि
में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था
बन गया है। आर्थिक मोर्चे के लिहाज
से देखें तो भारत पांचवें नंबर पर है
और सैनिक ताकत के लिहाज से

देखें तो चौथे नंबर है। चीन दुनिया के तीसरे नंबर की सैन्य शक्ति है। ऐसे में सीधी सैनिक कार्रवाई की अपनी सीमाएँ थीं। इसलिए विपक्षी दलों के तमाम उलाहनों और उकसावों के बावजूद मोदी सरकार गया। गलवान कांड के बाद से ही पड़ोसी होने के बावजूद दोनों देशों के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। इस बीच चीन को आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ा है। चीन को लगता है कि अगर भारत के साथ

वीजा नियम लागू कर दिए। चीनी नागरिकों के लिए सख्त वीजा नियम होने की वजह से चीन के विशेष इंजीनियरों और तकनीशियनों की भारत में आवाजाही पर एक तरह से पाबंदी ही लग गई। इसकी वजह से चीनी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण और निवेश पर लगाम लग गई। इसकी वजह से गलवान काड़ के बाद से ही चीनी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित अरबों डालर के निवेश की प्रक्रिया अटक गई। जिसका सीधा असर चीन की कंपनियों पर पड़ा और उन्हें आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ीं।

स्थित करीब 60 करोड़ डॉलर की अधिक की संपत्तियों को जब चीनी कंपनियों द्वारा खरीदा गया। इससे चीन के बड़े कारोबार को भारत में बड़ा असर लगा। वैसे चीन को यह लाने में भारत के राष्ट्रीय विदेश सलाहकार अजीत डोभाल 35 के विदेश मंत्री वांग यी के नियन्त्रण में चीनी बड़ी भूमिका



गांदरबल हमला चिन्ताजनक एवं चुनौतीपूर्ण घटना

लाला
जम्मू-

में 20 अक्टूबर रविवार रात को आतंकवादियों ने जिस तरह टारगेट किलिंग से एक कंस्ट्रक्शन प्रॉजेक्ट में काम कर रहे लोगों को निशाना बनाया, वह कई लिहाज से गंभीर चिन्ताजनक एवं चुनौतीपूर्ण घटना है। यह आतंक का अंधेरा फैलाने एवं अमन के उजाले को लीलने की गहरी साजिश है। यह जहां आतंकवादियों की बौखलाहट की निष्पत्ति है वहीं उनकी बदली प्राथमिकताओं की प्रतिबद्धता को भी दर्शता है। राज्य में टारगेट किलिंग की यह कोई नई घटना नहीं है बल्कि हाल ही के वर्षों में सुरक्षा बलों के कैम्पों से लेकर प्रवासी मजदूरों के घरों एवं कश्मीरी पंडितों पर ऐसे टारगेट किलिंग हमले होते रहे हैं जिसके पीछे आतंकी संगठनों की हताशा ही दिखाई देती है। टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति एवं आतंक फैलाने की नई साजिश है। अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद से ही टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। वर्ष 2022 और 2023 में आतंकियों ने न केवल कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया बल्कि प्रवासी मजदूरों की भी लक्षित हत्याएं की। चुनाव में बाधा डालने के उनके तमाम प्रयास निष्पल हो जाने, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक होने और इनमें लोगों की भागीदारी के भी रेकॉर्ड बनने से आतंकवादी हताश एवं निराश हो गये। पाकिस्तान बौखला गया। अब आतंकी तत्वों ने

अंजाम देकर यह जताने का प्रयास किया है कि वे जनादेश के तहत बनी इस सरकार की राह में अड़ंगा डालने का हरसंभव प्रयास करते रहेंगे, अशांति एवं आतंक फैलाते रहेंगे। लेकिन इन चुनौतियों को निस्तेज करने के लिये प्रातं एवं केन्द्र सरकार को कमर कसनी होगी। सुरक्षा बलों को नये तेवर दिखाने होंगे। लक्षित हत्याएं न केवल पीड़ितों और उनके परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाती हैं, बल्कि जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी गहरा झटका देती है। ये हत्याएं न केवल जम्मू-कश्मीर के समाज के विविध ताने-बाने को कमजोर करती हैं, बल्कि घाटी में रहने वाले गैर-स्थानीय और अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा भी पैदा करती हैं। ये हत्याएं विकास को अवरुद्ध करती है, बल्कि उद्योग, व्यापार, पर्यटन एवं सौहार्द को भी खण्डित करती है। सुरक्षा बलों पर विभाजनकारी एवं आतंकी ताकतों के खिलाफ अपना दृढ़ रुख बनाए रखने का दायित्व है, जिसे संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने में स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग से बल मिलता है। जबकि घाटी में शांति ने प्रगति की है, इस नाजुक संतुलन को बाधित करने के किसी भी प्रयास का सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों, दोनों द्वारा कड़ा विरोध किया जाना

विकास की गंगा प्रवहमान रही है। सुरक्षा बलों की सतर्कता से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में आई कमी और आम जनजीवन पर उनके घटते असर से चिंतित आतंकी आकाओं ने आम वुनावों के दरम्यान अपनी सक्रियता बढ़ा दी, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाये। अब मौका मिलते ही उन्होंने ऐसे इलाकों को चुना है जहां सुरक्षा बलों की तैनाती कम और मुश्किल थी। टारगेटेड एटैक के जरिए बाहरी लोगों को निशाना बनाया गया ताकि उनमें घबराहट फैले, अफरा-तफरी मचे और पर्यटकों का आना कम हो। इसीलिये आतंकियों ने इस बार हमले के लिए श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच बनाई जा रही जेड-मोड टनल का काम कर रहे लोगों को चुना गया। यह टनल न केवल जम्मू-कश्मीर के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इण्नीतिक तौर पर भी खासी अहमियत रखती है। इसके निर्माण से श्रीनगर और करगिल के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा और श्रीनगर व लेह के बीच की यात्रा में लगने वाला समय कम हो जाएगा। यही नहीं, इस टनल के जरिए पर्यटकों के पसंदीदा शहर सोनमर्ग की हर मौसम में सुविधाजनक पहुंची सुनिश्चित की जा सकेगी।

गांदरबल का हमला आतंकियों की एक बड़ी सफलता है, कश्मीर में आतंक-अशांति फैलाने और विकास

पा गाता पा जपलक्ष्म पर्ण पा साजिश है। जाहिर है, पाकिस्तान ने जमीन पर बैठे आतंकवादी तत्त्वों ने इस एक हमले के जरिए कई उद्देश्य पूरे करने की कोशिश की है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी में एक बड़ी आतंकी घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाना हमारे लिये चिन्ता वाला साथ चेतावनी भी है। यह घटना चेता भी रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्वाचन क्षेत्र गांदरबल में केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टनल प्रोजेक्ट में कार्यरत सात प्रवार्सी श्रमिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। मृतकों में एक स्थानीय डॉक्टर भी शामिल था। मरने वालों में पंजाब बिहार और कटुआ के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। कई श्रमिकों वाले घायल होने की खबर है जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये सभी श्रमिक काम खत्म करने वाले दो मेस में खाना खाने बैठे थे। तभी आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। निश्चितरूप से यह आतंकवादियों की कायराना एवं शर्मनाक करतूत है। इस घटना से चार दिन पहले शोपियाँ में बिहार के एक मजदूर की हत्या कर दी थी। ये हत्याएं आतंकवाद की अंधाधुंध हिस्क एवं आतंकी प्रकृति का उजागर करती हैं जो अपने रास्ते में किसी को भी नहीं छोड़ते। निर्दोष नागरिकों की बेवजह हत्या किर्सा एक परिवार के किसी प्रियजन के ही नहीं छीनता बल्कि उन लोगों में

यो लदव जब पुरुष त नूर नहा कहा जा सकता। लेकिन इसके लिये सन्देह एवं शंकाओं के धेरों को तोड़ना होगा। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाए के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवान लगातार मुहिम चला रहे हैं उनके प्रयासों को बिना राजनीति किये तीक्ष्ण एवं तीव्र करना होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। जाहिर है पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के लिए सीमा पार से साजिशें कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षाबलों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आतंकवादी कश्मीर घाटी में फिर ऐसी आतंकी घटना की पुनरावृत्ति न कर पाए। जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर यह संदेश दिया कि घाटी में लोकतंत्र महके, ना कि ढहके। यह जनादेश आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्ति की चाहत का परिणाम है। राज्य की जनता ने अपनी उम्मीदों को लेकर सरकार चुनी और नैशनल कार्फ्रैंस पर भरोसा जताया। नई सरकार के सामने जनता की उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती तो है ही, सबसे बड़ी चुनौती तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करना और ऐसा वातावरण सृजित करना है जिसमें आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे और इस क्षेत्र में विकास की धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले।

रियल एस्टेट को डेटा सुरक्षा कानून पर ध्यान देने की आवश्यकता

५८

तजा स डाइटल हाता दुनिया में, व्यवसायों को बढ़ावा दने के लिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है। रियल एस्टेट उद्योग कोई अपवाद नहीं है, जिसमें खरीद और बिक्री तेजी से ऑनलाइन हो रही है। डिजिटल क्रांति को देखते हुए, रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा संभावित गोपनीयता उल्लंघनों के खिलाफ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत डेटा के ऑनलाइन प्रसंस्करण को विनियमित करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इस संदर्भ में एक बहुत जरूरी कानून है। भले ही यह वर्तमान में लागू नहीं है और इसमें नियमों और अधिकारों को जारी करने की समयसीमा जैसे विशिष्ट है, लाकन रियल एस्टेट उद्योग के भौतिक और डिजिटल दोनों हिस्सों को नियमों के लागू होने के बाद इसके प्रावधानों का पालन करना होगा। DPDG अनुपालन आवश्यकताओं, डेटा हैंडलिंग प्रथाओं और डेटा फिल्चियरी, डेटा प्रिंसिपल और डेटा प्रोसेसर के लिए सम्भावित कानूनी निहितार्थ में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। इसके लिए, यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43ए और 87(2)(बी) को निरस्त करने और इसे डीपीडीपीए की धारा 44(2) से बदलने का प्रस्ताव करता है। परिणामस्वरूप, आईटी (उचित सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 जो वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है

का भा निरस्त कर दिया जाएगा।
क्योंकि उन्हें आईटी अधिनियम के
तहत अधिसूचित किया गया था।
रियल एस्टेट के संदर्भ में डेटा
फिल्चुसरी में रियल एस्टेट फर्म
और पोर्टल जैसे कि हाउसिंग डॉटकॉम,
मैजिकब्रिक्स या जस्टडायल
जैसी वेबसाइटें आदि शामिल होंगी।
इसी तरह, डेटा प्रिसिपल घर
खरीदार, किराएदार, संपत्ति विक्रेता,
मकान मालिक, एजेंट, ब्रॉकर,
डेवलपर, बिल्डर आदि होंगे, जिनका
डेटा उनकी सहमति से एकत्र किया
जाएगा। डेटा प्रोसेसर कोई भी
थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस
कंपनी या डेटा फिल्चुसरी की
इन-हाउस प्रोग्रामिंग ठीम होगी।
अनुपालन आवश्यकताएँ शीर्ष
न्यायालय के ऐतिहासिक पुट्टस्वामी
निर्णय के परिणामस्वरूप, गोपनीयता
के आधारभूत सिद्धांत जैसे सहमति

व्याकृतगत डेटा का वध और पारदर्शा उपयोग, उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनीकरण, डेटा सटीकता, भंडारण सीमा, उचित सुरक्षा उपाय और जवाबदेही ने DPDP अधिनियम में अपना रास्ता खोज लिया है। सहमति के लिए वैध और पारदर्शी नोटिस, धारा 5 रियल एस्टेट कंपनियों को कई भाषाओं में स्पष्ट गोपनीयता नोटिस प्रदान करते हुए डेटा प्रिंसिपलों से स्पष्ट रूप से सहमति प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें सहमति के प्रमाण को पुनर्प्राप्ति योग्य तरीके से संग्रहीत करना होगा। धारा 6(4), और डेटा प्रिंसिपलों को डेटा के उद्देश्य, प्रकार और इच्छित उपयोग के बारे में सूचित करना होगा। प्रसंस्करण में संग्रह, भंडारण के साथ-साथ उपयोग भी शामिल होगा। उदाहरण के लिए, एक्स नाम की एक छात्रा साउथ दिल्ली में कियाये

जो सपात्तया का तलाश करने के लिए JustDial के मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करती है। अपने Google खाते से पंजीकरण करके, यूक्स अपने अनुरोध को संभालने के लिए JustDial को अपने व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की सहमति देती है। इसलिए जस्टडायल से व्यक्तिगत डेटा के लिए अनुरोध के नाथ या उससे पहले एक्स को एक भविष्युचना दी जानी चाहिए जिसमें एकत्रित की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी की रूपरेखा हो — जैसे के उसका स्थान, फोन नंबर, Google प्रोफाइल इत्यादि — और इसे कैसे संसाधित किया जाएगा। उद्देश्य— अनुकूल दृष्टिकोण, धारा 6(1) रियल एस्टेट कंपनियों को डेटा प्रोसेसिंग को केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक तक नीमित रखना चाहिए विस्तृत डेटा

हडालग प्रथमा से आधक काद्रत दृष्टिकोण में संक्रमण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब घर खरीदने वाला एक्स हाउसिंग पोर्टल ऐप वाई डाउनलोड करता है, तो यह एक्स से उसके स्थान तक पहुँचने के लिए उसके डेटा को संसाधित करने की अनुमति माँगता है ताकि आस-पास बिक्री के लिए घरों की सिफारिशों की जा सकें, और उसके फोन पर संपर्क सूची तक पहुँच हो सके। एक्स जवाब देता है और

दाना अनुराधा पर अपना सहमति प्रदान करता है। DPDP में संदर्भित गोपनीयता सिद्धांतों के परिणामस्वरूप, उसकी सहमति केवल उसके स्थान को संसाधित करने तक सीमित होगी क्योंकि संपर्क में पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य करता है। इसलिए, DPDP की सख्त डेटा सुरक्षा आवश्यकताएँ व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रूप से संभालना सुनिश्चित करके RERA के पारदर्शिता लक्ष्यों को पूरक करेंगी। किसी न्यासी द्वारा दायित्वों का पालन न करने पर संभावित रूप से DPDP की अनुसूची I के अनुरूप निर्णय और/या दंड हो सकता है। प्रभाव और चुनौतियाँ DPDP के कार्यान्वयन से रियल एस्टेट उद्योग की डेटा हैंडलिंग प्रथाओं में सुरक्षा उपायों और जवाबदेही में काफी संपर्क होगा।



लिए उसके डेटा को संसाधित करने की अनुमति माँगता है ताकि आस-पास बिक्री के लिए घरों की सिफारिशों की जा सकें, और उसके फोन पर संपर्क सूची तक पहुँच हो सके। एक्स जवाब देता है और सूची किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। भूल जाने का अधिकार, ए आरा 12(1) डेटा प्रिंसिपल अपने डेटा को सही करने या मिटाने के हकदार हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई किराएदार अब अपनी संपत्ति को

भाजपा ने फूलपुर से दीपक पटेल को बनाया प्रत्याशी

प्रयागराज, संवाददाता। भाजपा ने फूलपुर विधानसभा उप चुनाव के लिए दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही कई दिनों से चल रही अटकलों पर विधाम लग गया है। दीपक पटेल कर्णना से 2012 से 2017 तक बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। दीपक की माता केशरी देवी पटेल फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से 2019 में भाजपा से सांसद चुनी गई थीं। दीपक पटेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और फूलपुर की पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के पुत्र हैं। वे बसपा से 2012 में कर्णना विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने सपा प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह को पराजित किया था। 2017 में बसपा ने फिर एक बार कर्णना विधानसभा से दीपक को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह जीत नहीं पाए। दीपक 2018 में भाजपा में शामिल हुए।

भाजपाइयों ने दी उन्हें अग्रिम जीत की बधाई।

आगामी 13 नवंबर को हाने वाले फूलपुर उप विधानसभा के लिए दीपक पटेल को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दीपक को बधाई दी। भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा और जिला अध्यक्ष रामगापार के पास पटेल को प्रत्याशी बनायी दी। भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा और हर्षवर्धन जायपेही, युजुर सापाद में, सुनेंद्र योधी, जिला पंचायत अध्यक्ष के संसदीय अधिकारी कहा कि भाजपा फूलपुर में प्रबंध बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही कुंज विहारी मिश्रा, वरुण केसरवानी, राजेश केसरवानी, रमेश पासी देवेश सिंह विवेक मिश्रा, बुजेश त्रिपाठी विवेक अग्रवाल, राजू पाठक जिराव मिश्रा राधेवेंद्र सिंह प्रशांत शुक्ला, राकेश भारती राजेश गोंड, कुलदीप मिश्रा दीप द्विवेदी आदि ने दीपक को बधाई दी।

सपा ने मुज्जबा और बसपा ने जितेंद्र सिंह पर लगाया है दाव।

फूलपुर उप चुनाव के लिए अब सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। सपा ने पूर्व विधायक मुज्जबा लिंग्ही को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुज्जबा 2022 में भी सपा से प्रत्याशी थे और भाजपा प्रत्याशी प्रवीन पटेल से पराजित हो गए थे। मुज्जबा ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। इसी तरह बसपा ने जितेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफतार

गोरखपुर, संवाददाता। रेलवे युग डी में नौकरी लगवाने के नाम पर छह लाख रुपये लेकर फूर्जी नियुक्ति पत्र देने व बापास मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को झंगाहा पुलिस ने बुधवार को गिरफतार कर लिया।

तेंदुआ खुर्द गांव निवासी विनय कुमार शुक्ला उर्फ पुनीत शुक्ला को पुलिस ने भोपा बाजार चाराहे से चार पहिया वाहन के साथ गिरफतार किया। आधार कार्ड और सारे कागज पर वाहन को एम्बी एकट के तहत बदल लिया।

बमबाजी से दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

भदोही, संवाददाता। ज्ञानपुर के गोपीगंज कोतवाली स्थित एनीपुर गांव निवासी डीघ ब्लॉक संचालन समिति प्रमुख मनोज मिश्रा के आवास पर बाइक सवार तीन हमलावारों ने बम से हमला कर दिया। बम उनके दो मंजिले आवास की दूसरी छत के दिवाल पर टकराई। बताया जा रहा है कि हमलावारों का निशाना मनोज मिश्रा के कमरे में लगी एसी के बाहरी की थी। आरोप है कि विनय ने लोगों से 4.90 लाख रुपये खाते में, 1.10 लाख रुपये नकद, वहीं दूसरी तरफ पुलिस पटाखे से हमला किए जाना बता रही है। मामले में

उत्तर कर एक के बाद एक दो बम डीघ ब्लॉक संचालन समिति प्रमुख मनोज मिश्रा के आवास की ओर फेंकता है। नियाद पार्टी के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे व डीघ ब्लॉक के प्रमुख मनोज मिश्रा इस समय दुष्कर्म समेत अन्य मामले में जेल में बंद हैं। डीघ ब्लॉक का संचालन समिति की कर रही है। संचालन समिति के प्रमुख मनोज मिश्रा के भतीजे व डीघ ब्लॉक के प्रमुख मनोज मिश्रा के बाहरी तत्काल इसकी सूचना रणनीती चौकी प्रभारी को दी। चौकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। बताया जा रहा है कि हमलावारों का निशाना मनोज

मिश्रा के कमरे में लगी एसी के बाहरी हिस्से पर था, लेकिन एक बम एसी के मात्र एक की ऊपर फेंकता है। जिसके बाद तीनों बाइक से हाईवे का रोड पकड़कर फरार हो जाते हैं। बम के हुए तेज धमाके से नियाद पर दिवाल पर बने हुए हैं। वहीं आवास के बाहर शीशों का छर्चा बिखरा पाया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। इस संबंध में एसी 2.0 मीनाकी कात्यायन का कहना है कि शरारी तत्वों ने आवास पर पटाखा फेंका है। सीसीटीवी से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। जांच की जारी है।

शरारीर लाइसेंस हो गया था निरस्त।

पुलिस पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर अपराध के लिए अब उनके बेटे विष्णु को 2021 में गिरफतार किए गए। उसके बाद से ही दोनों अलग-अलग जेल में बंद हैं। इधर, उनकी मुश्किल और बढ़ती जा रही है। युवावार को गोपीगंज कोतवाली में बाप-बेटे के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट की अवालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को विजय मिश्रा को 21 जून 2024 को नोटिस तामील कराते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई। निरस्तदार की संपत्ति हुडपने, हथ्या, लूट, डकेटी समेत कुल तीन दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा इस समय जेल में बंद हैं।

बोले अधिकारी

वरुण को साक करने के लिए एक संस्था के साथ अनुबंध किया गया है। जो वरुण का बाप वरुण को बोर्ड, फैसले चार और टाइटल बनाने में बताया किया जाता है। इसे लाइसेंस को बोर्ड, फैसले चार और टाइटल बनाने में बताया जाता है। कंपनी के एक सदस्य ने बताया कि हमारा ये प्रोजेक्ट वाराणसी में एक साल से चल रहा है।

रिसाइकिल प्लास्टिक से बने बोर्ड, फैसले चार और टाइल्स

प्लास्टिक का एकत्र करने के बाद उसे शेड में ड्राई किया जाता है।

इससे नियामनी के लिए 2023 में योजना बनी। प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए एक संस्था के साथ अनुबंध किया गया है। आरोप है कि अनियमित नियुक्ति के बाद प्रयाण नदी को रोक दिया गया है। आईटीआई और सेवायोजन के रिक्त पदों पर भर्ती की जिले के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए एक संस्था के साथ अनुबंध किया गया है। आरोप है कि अनियमित नियुक्ति के बाद वरुण को रोक दिया गया है। आईटीआई और सेवायोजन के रिक्त पदों पर भर्ती की जिले के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत्रीय संवायोजन अधिकारियों को तत्कालीन नियोजन के लिए 2023 में योजना बनी।

प्रयाणांशी और क्षेत